(b) The State of Jammu & Kashmir is an integral part of India.

Impact of peace talks between LTTE and Sri Lankan Government

4390. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government of India are examining the impact of peace talks between the LTTE and the Sri Lankan Government on the case against the LTTE leader and the consequence of formal LTTE control of the north and east of Colombo following peace settlement and the resultant unease to be caused by the existence of an LTTE-run province just of the Tamil Nadu coast; and

a2 (b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAV SINH SOLANKI): (a) and (b) There are no reports of any peace talks between the LTTE and the Sri Lankan Government so far, though there are reports of indirect contacts between them. India favours a political settlement to the ethnic problem within the unity and territorial integrity of Sri Lanka, that will include those Tamil groups who have eschewed violence. We believe that the political framework created by the 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution based on the provisions of the Indo-Sri Lanka Agreement remains a constructive point of reference in any future negotiations.

*Previously Unstarred Question 3507 transferred from the 25th March, 1992.

जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा

4391. **श्री छोटूभाई पटेल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान जर्मनी के चांसलर द्वारा भारत की यात्रा किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) जी हां।

(ख) जर्मनी के चांसलर डाक्टर हेल्मट कोहल वर्ष 1990 का अन्तर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरु पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अक्तूबर, 1992 में भारत आएंगे।

(ग) चांसलर कोहल के साथ उनकी आगामी यात्रा के दौरान जो चर्चाएं होंगी उनमें द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा और पारस्परिक हित और पारस्परिक लाभ के सभी क्षेत्रों में भारत-जर्मन संबंधों को मजबूत करने के लिए उपायों पर चर्चा शामिल होगी।

Meeting of Heads to Discuss Environment and Development

*4392. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a meeting of the heads of Government will be held in April this year to discuss 'Environment and Development';

(b) whether the conference is expected to identify and explore the problems that effect environment and development and linkages between the two; and

(c) what suggestions Government have offered for consideration by the proposed meeting?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAV SINH SOLANKI): (a) The UN Conference on Environment and Development at the level of Heads of State/Government will be held in Brazil in June this year.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government have offered various suggestions during the preparatory process including a Draft Convention on Climate Change. Our

general approach is that environmental degradation results from the wide global disparities in patterns of consumption and production. In developing countries, economic and social development is a necessary pre-requisite for environmental protection. The international agenda should simultaneously address issues of environment and development and should focus adquately on environmental problems of specific relevance to developing countries. A meaningful programme of international cooperation should be based on provision of adequate, new and additional financial resources for developing countries and transfer of technology to them on a non-commercial or preferential basis.

मास्को में हुई पश्चिम शान्ति वार्ता

4393. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटूभाई पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में मास्को में हुई पश्चिम शान्ति वार्ता में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने इस वार्ता में क्या भूमिका निभाई?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों को दिए गए ऋण

4394. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटू भाई पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा दक्षिण एशिया के अन्य देशों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार ऋण लेने वाले देशों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई तथा उन्होंने कितनी ऋण राशि लौटाई;

(ग) क्या ये ऋण उन देशों की विशेष परियोजनाओं के लिए थे; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गई है। [**नीचे देखिए**]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दक्षिण एशिया के देशों को दिए गए ऋण, वितरित की गई राशि और संबंधित देशों द्वारा 31 दिसम्बर, 1991 तक पुनर्भुगतान की गई राशि का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:—

वर्ष	दिया गया ऋण	वितरित की गई राशि	पुनर्भुगतान की गई राशि
नेपाल			
1989-90	5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये
1990-91	39 करोड़ रुपये	39 करोड़ रुपये	39 करोड़ रुपये
1991-92 (31.12.91 तक)	55 करोड़ रुपये	55 करोड़ रुपये	55 करोड़ रुपये
कुल :	99 करोड़ रुपये	99 करोड़ रुपये	99 करोड़ रुपये

यह भारत और नेपाल के बीच परिक्रामी ऋण करार के अनुसार था।

श्रीलंका

1987 के ऋण करार के अन्तर्गत श्रीलंका को 25 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। 31.12.91 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका को 4.46 करोड़ रुपये की वास्तविक राशि वितरित की गई थी और कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

बंगला देश

भारत से पूंजीगत वस्तुओं तथा मशीनरी के आयात के लिए 1991 के करार के द्वारा बंगलादेश को 30